



16. सातवाहन राज्यव्यवस्था

सातवाहनो का शासन दक्कन मे था । ये उन सभी भौतिक उपादानों से सज्जित थे जो इनसे पहले उत्तर भारत में शासन करनेवाले भौर्य राजाओं के पास थे । अर्थात् इनके राज्य में सिक्को और लोहे के औजारों का भरपूर उपयोग होता था । इनके शासन की एक अन्य विशेषता यह थी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के साथ इनके राज्य का वृहत व्यापार था । इसके परिणामस्वरूप रोम के सिक्के यहा प्रचुर प्रमाण में पहुंचते थे, जिससे दक्कन मे बडे पैमाने पर शहरी बस्तियों की स्थापना हुई । इन तमाम बातों ने नई समस्याओ को जन्म दिया, जिनका समाधान ढूढना इनके शासन का काम था ।

सातवाहन आर्येतर जाति के थे और इनकी परंपराएँ मातृवशीय थी । ये ब्राह्मण सस्कृति को अगीकार करनेवाले दक्कन के सबसे पहले राजवशों मे थे । एक बार नए सस्कारों को ग्रहण करने के बाद ये लोग वर्णव्यवस्था के कट्टर समर्थकों के रूप मे आगे आए, किंतु बौद्धधर्म से भी इनका विरोध नही था । अभिलेखों से मालूम होता है कि ये बौद्ध भिक्षुओ तथा ब्राह्मणों को द्रव्य और भूमिअनुदान देनेवाले प्राचीनतम शासक थे । इन अनुदानों के फलस्वरूप बौद्ध भिक्षु और ब्राह्मण दोनों समान रूप से सातवाहन राज्यव्यवस्था मे महत्त्वपूर्ण तत्व बन गए । भौर्य शासन के अनुभवों से लाभ उठाकर सातवाहनों ने अपने पैर उन क्षेत्रों पर जमाएँ जो किसी हद तक ठीक से आबाद थे और जिन पर बहुत-से छोटे-छोटे राजाओ और सरदारों का शासन था । जिस शासनपद्धति का उन्होंने विकास किया उसकी प्रकृति स्वदेशी थी और भारत-यूनानियों, शकों, पार्थियनों और कुषाणों द्वारा भारत मे लाई गई राज्यव्यवस्था से सर्वथा भिन्न थी ।

मैसूर में प्राप्त शिलालेखों और आंध्रप्रदेश के अमरावती मे प्राप्त स्तंभलेख के एक टुकडे से स्पष्ट है कि इन क्षेत्रों के नरेश अशोक की शासनपद्धति से अवगत थे । स्वभावतः, इसके कुछेक तत्व सातवाहनो के अधीन दक्कन के पश्चिमी हिस्से में भी कायम रहे । अशोक की तरह ही प्रारंभिक सातवाहन शासक राजा कहे जाते थे । यद्यपि गौतमीपुत्र शातकर्णी की माता गौतमी बलश्री का दावा है कि उसके पुत्र और पौत्र महाराज हैं, किंतु गौतमीपुत्र और वासिष्ठीपुत्र पुलुमावि में से किसी ने

भी वास्तव में यह उपाधि धारण नहीं की। साथ ही इन शासकों ने वे आडंबरपूर्ण उपाधिया भी धारण नहीं की जो कृपाण राजाओं की विशेषता थी। इसके अतिरिक्त, इन राजाओं ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अपने आदेशों की सूचना उसी मुहावरे और उसी प्राकृत भाषा में दी है जो अशोक के शासन में प्रचलित थे। हा, सातवाहनो के ये अधिकारी कुमार, आर्यपुत्र या अशोक के अधिकारियों की तरह महामात्र नहीं, बल्कि अमात्य कहे जाते थे।

सातवाहन राज्य अशोक के राज्य की ही तरह आहारों या जिलों में बटा हुआ था। अशोक के अभिलेखों में आहारों के नाम नहीं दिए गए हैं, यद्यपि जिन अभिलेखों में इनका उल्लेख मिलता है उनके प्राप्तस्थानों की दृष्टि से सोचें तो लगता है कि ये आहार मध्य प्रदेश तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में पडते थे। किंतु सातवाहन-अभिलेखों में गोवर्धन आहार और कुछ अन्य आहारों का उल्लेख बहुधा हुआ है। यह प्रशासनिक इकाई वाकाटक राज्य में कायम रही, और गुप्तकाल तथा गुप्तोत्तर काल के अभिलेखों के अनुसार इन कालों में महाराष्ट्र और गुजरात में भी प्रचलित थी।² तीसरी शताब्दी के प्रथम चरण के एक सातवाहन पुरालेख में लगता है कि आहार और जनपद एक ही थे।³ जनपद का उल्लेख कौटिलीय अर्थशास्त्र में भी हुआ है और अशोक के अभिलेखों में भी। लेकिन नाम की समानता से ऐसा नहीं माना जा सकता कि सातवाहन जनपद (आहार) और अशोककालीन जनपद के आकार भी समान थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित जनपद के आकार को यदि लिया जाए तो अशोककालीन जनपद में सभवतः 3200 गाव होते थे।⁴ इस प्रकार यह निश्चय ही बहुत बड़ी इकाई थी।

यद्यपि कौटिल्य ने महामात्रों का उल्लेख विरल स्थानों पर ही किया है, किंतु अशोक के अधीन महामात्र कहे जानेवाले अधिकारियों का एक सर्गठित संवर्ग (काडर) था, जिसके सदस्यों को तरह-तरह के कार्यों में लगाया जाता था। उनका उल्लेख सातवाहन अभिलेखों में भी हुआ है, और एक प्रसंग में वह बौद्ध भिक्षुओं की देखरेख के लिए जिम्मेदार अधिकारी जान पडता है।⁵ इस तरह मोटे तौर पर उसकी तुलना अशोक के धम्ममहामात्र से की जा सकती है। लेकिन स्पष्ट है कि सातवाहन राज्य में महामात्र नाम की संस्था उतनी व्यापक और महत्त्वपूर्ण नहीं थी। अशोक के महामात्रों वाला स्थान शायद सातवाहनो के अमात्यों या अमचों को प्राप्त था। भूमि अनुदानों या गुफा अनुदानों से संबंधित सभी राजादेशों की सूचना सातवाहन शासक अमात्यों या अमचों को ही देते थे। जातकों में अमात्यों का उल्लेख सलाहकारों या मंत्रियों के रूप में हुआ है, लेकिन इनके बारे में सबसे विस्तृत जानकारी कौटिलीय 'अर्थशास्त्र' से मिलती है, जिसमें इनका उल्लेख अधिकारियों के ऐसे संवर्ग (काडर) के रूप में हुआ है जिसमें से अन्य सभी उच्च पदाधिकारी लिए जाते हैं। विचित्र बात है कि अधिकारियों के इस महत्त्वपूर्ण वर्ग

का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं हुआ है। जहां तक अभिलेखों का संबंध है, इनका उल्लेख सबसे पहले सातवाहनों के ही राज्य में मिलता है। इन अभिलेखों से प्रकट होता है कि गुप्तकाल की तरह सातवाहनों के अधीन अमात्य पद वशानुगत नहीं था। विष्णुपालित,⁶ शिवदत्त,⁷ और श्यामक,⁸ कम से कम इन तीन व्यक्तियों ने गौतमीपुत्र शातकर्णी के राज्यकाल में गोवर्धन आहार में अमात्य के पद पर काम किया। फिर, वासिष्ठीपुत्र पुलुमावि के राजत्वकाल में 152 ई. में उसी स्थान पर अमान्य शिवस्फोद को कार्य करते देखते हैं।⁹ 28 वर्षों के दौरान एक ही स्थान पर कार्य करनेवाले इन चार अधिकारियों के नामों से प्रकट होता है कि ये एक परिवार के भी नहीं थे। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक अमात्यों के भी उल्लेख मिलते हैं। जैसे परिगुप्त, जो शायद गौतमीपुत्र शातकर्णी¹⁰ के अधीन काम करता था, और सनेरक¹¹, सर्वाक्षदलन तथा विष्णुपालि, जो कदाचित् वासिष्ठीपुत्र शातकर्णी के अधीन काम करते थे।¹² किंतु इनमें से किसी भी उल्लेख से अमात्यपद के वशानुगत रूप की जानकारी नहीं मिलती। कुछ अभिलेखों में राजामात्य का उल्लेख अवश्य हुआ है, पर अभी तक गुप्तकालीन कुमारामात्य का जिज्ञासु किसी भी सातवाहन अभिलेख में देखने को नहीं मिला है। कुल मिलाकर, अमात्य सातवाहन राज्यव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग थे। उन्हें वही स्थान प्राप्त था जो अशोक की शासनव्यवस्था में महामंत्रियों को और गुप्तों की राज्यव्यवस्था में कुमारामात्यों को था। जहां तक इनके कार्यों का संबंध है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे प्रकट होता हो कि ये सलाहकार या मंत्री का कार्य करते थे। कम से कम वे किसी सर्गाटित निकाय के रूप में कार्य करते तो नहीं ही प्रतीत होते। लेकिन व्यक्तिगत रूप से वे प्राणीय शासकों (गवर्नर), कोषागारियों, भूमिदान निष्पादकों (एक्जिक्यूटिव) आदि अनेक हैसियतों में कार्य करते थे।

अनेक अधिकारी शासनपत्र (लैंड चार्टर) लिखने से सवद्ध थे। एक प्रसंग में हम अमात्य को, दूसरे में प्रतीहार (जिसका प्रथम उल्लेख सातवाहन अभिलेखों में ही हुआ है) को और तीसरे में महासेनापति को शासनपत्र लेखक के रूप में देखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह काम किसी एक अधिकारी के जिम्मे नहीं था, यद्यपि गुप्तोत्तर काल में यह काम मुख्यतः साधिबिग्रहिक ही करना था। सातवाहन राजे शासनपत्रों की देखरेख करनेवाले अधिकारी भी रखते थे, जिन्हें पट्टिकापालक कहते थे।³ इनके अलावा, शासनपत्रों को उत्कीर्ण करनेवाले और भोक्ताओं को अनुदानों की सूचना देने वाले अधिकारी भी रखे जाते थे। लेकिन अशोक के राज्य के राजक, प्रादेशिक, प्रतिवेदिक, पुरुष, मुक्त, आदि किसी अधिकारी का उल्लेख सातवाहन-अभिलेखों में नहीं मिलता। यदि हम इस नकारात्मक साक्ष्य को प्रमाण मानें तो कहना होगा कि सातवाहन शासनतंत्र काफी मरल था।

संभव है, सातवाहन राज्य में अधिकारियों को वेतन नकद दिया जाता रहा हो। कौटिल्य द्वारा 'अर्थशास्त्र' में अनुशासित इस वेतनविधि का चलन सातवाहन राज्य में था, इसकी पुष्टि कार्पाणो के उन विभिन्न आंकड़ों की लंबी सूची से होती है जो नागनिका के नागाघाट गुफालेख¹⁴ में तथा अन्यत्र दिए गए हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि विभिन्न यज्ञों के अवसर पर दी गई दक्षिणा की राशि 1,48,000 कार्पाण¹⁵ से भी अधिक थी। नकद भुगतान की पुष्टि रांगे, पोटीन, तांबे और चांदी के उन असख्य सिक्कों से होती है जो मुख्यतः महाराष्ट्र में, लेकिन किसी हद तक आंध्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मिले हैं। सातवाहन क्षेत्र में रोम की स्वर्णमुद्राएं प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई हैं। इन मुद्राओं का उपयोग शायद बड़े-बड़े सौदों में या धनसंग्रह के लिए किया जाता होगा। लेकिन सातवाहन सिक्के स्पष्ट ही रोजमर्रा के सौदों में, जिनमें अधिकारियों को वेतन की अदायगी भी शामिल थी, इस्तेमाल किए जाते होंगे। किंतु इस सबसे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि अधिकारियों को जिसों के रूप में वेतन दिया ही नहीं जाता होगा।

सातवाहनो की राजस्वव्यवस्था का कुछ अंदाजा धार्मिक अनुदानों में दिए गए गांवों में प्रदत्त राजस्व विषयक रियायतों से लगाया जा सकता है। कर बसे हुए गांवों या आबाद जमीन पर लगाए जाते थे। नमक सहित समस्त खनिज संपदा राजा की मानी जाती थी। राज्याधिकारियों, पुलिस और सैनिकों को ठहराने का भार किसानों के सिर डाला जा सकता था और इन सरकारी अमलों का खाना खर्चा या जिस तंत्र के ये अंग थे उसके संचालन का खर्च किसानों से वसूल किया जा सकता था। देय-मेय¹⁶ और भोग¹⁷—जैसे शब्द उपज में राजा के हिस्से के द्योतक हैं। राजा कारुकर¹⁸ भी प्राप्त करता था। इस शब्द का अर्थ कारीगरों से उगाहा गया कर लगाया जा सकता है। यदि ये कारीगर धर्मशास्त्रों की व्यवस्था के अनुसार महीने में एक दिन अपने सरदार (यहां महारठी वासिष्ठीपुत्र सोमदेव)¹⁹ के लिए काम नहीं करते होंगे तो संभव है कि कर की नकद अदायगी करते होंगे। ऐसा मालूम होता है कि राजस्व नकद और माल दोनों रूपों में वसूल किया जाता होगा। साधारण धातु के जो बहुत-से सिक्के मिले हैं उनसे लगता है कि नकद वसूली कम नहीं होती थी। इस बात का समर्थन कोषपाल (ट्रेजरर) के लिए हैरिण्यक, यानी स्वर्णरक्षक, शब्द के प्रयोग से भी होता है।²⁰

यहां पर इस बात का विचार करना अनुचित न होगा कि सातवाहन राजनीतिक संगठन पर दकन के उन्नतिशील कलाकौशल और बढ़ते हुए वाणिज्य-व्यापार के क्या प्रभाव हुए। एक अभिलेख में एक अधिदर्शक (ओवरसियर) का जिक्र है, जिसकी देखरेख में कारीगरों ने एक गुफा बनाई।²¹ अधिदर्शकों (ओवरसियरों) के इस वर्ग में बौद्ध भिक्षु, गुरुजन, व्यापारी आदि सम्मिलित थे। इन्हे नवकर्म्मिक और उपरिहित²² जैसी अनेक राजाओं से अभिहित किया जाता था। राज्य से इनका कोई

वास्ता या या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। अभिलेखों में बहुधा उल्लिखित विभिन्न प्रकार के कारीगरों और व्यापारियों (नैगमों) के समूहों से व्यवहार करने के लिए सातवाहन राजाओं ने कैसा सगठन कायम कर रखा था, इसका कोई संकेत नहीं मिलता है। लेकिन इतना निश्चित है कि उन्हें अपनी श्रेणियाँ (गिल्ड) बनाने की पूरी स्वतंत्रता थी, और राजपरिवार के सदस्य भी इन श्रेणियों में धर्मस्व राशियाँ जमा किया करते थे।

बौद्ध भिक्षुओं और संस्थाओं को दिए गए जिन अनुदानों का उल्लेख 'ल्यूडर्स लिस्ट' में हुआ है उनके अवलोकन से यह धारणा बनती है कि भरहुत और साची में अधिकतर दान कारीगरों और गौधक (जिससे गांधी उपाधि निकली) कहे जाने वाले एक व्यापारी वर्ग द्वारा दिए गए। लेकिन नासिक और जुन्नर गुफालेखों से प्रकट होता है कि बहुत-से व्यक्तिगत अनुदान नैकम या नैगम कहे जानेवाले व्यापारियों ने लिखे, हालाँकि दाताओं के रूप में गौधकों, सेठियों और सचबहों के नाम भी आए हैं। यदि व्यापारी धर्मघाते में इस तरह दिल खोलकर दान देते थे तो राज्य खुद अपने मामले में उन्हें कजूसी क्यों करने देता? कारीगरों और व्यापारियों से राजा को होनेवाली आय के प्रत्यक्ष साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं, किंतु कारुकर शब्द के प्रयोग से लगता है कि गाव में रहनेवाले कारीगरों को भी कर चुकाना होता था। घाटकर (फेरी ड्यूज), जिसे कुछ प्रसंगों में तो हम उजभदात²³ को वसूल करके भेजते देखते हैं, मुख्यतः व्यापारी ही देते होंगे। संभव है, सातवाहन राज्य के विभिन्न समुद्री बंदरगाहों में बने चुगीघरों की देखरेख के लिए चुगी अधिकारी भी रखे जाते होंगे, लेकिन हमें वास्तविक स्थिति जानने का कोई जरिया मालूम नहीं है।

सातवाहन राजा बड़े-बड़े सरकारी पदों पर शायद व्यापारियों को रखते थे। उनके अमात्यों के नामों—जैसे शिवगुप्त और परिगुप्त—से लगता है कि वे वैश्य थे। नगरव्यवस्था से व्यापारियों का घनिष्ठ संबंध दिखाई देता है। सातवाहन राज्य में इन नगरों की संख्या सबसे अधिक प्रतीत होती है। अभिलेखों में भरुच, सोपारा, कन्हैरी, यल्पाण, पैघन, तगर (तेर), जुन्नर, कर्ले, गोवर्धन, नासिक और धन्यकटक नाम आए हैं। उत्खननों से अन्य अनेक नगरीय या अर्धनगरीय वास्तियों का भी पता चलता है। ये हैं मस्की, ब्रह्मगिरि, चद्रबलि, ब्रह्मपुरी (कोल्हापुर), जोर्वे, कोडपुर, चहल, सगंकुल्लु, अमरावती, नागार्जुनकोंड आदि। हम इनमें अरिकमेदु को भी शामिल कर सकते हैं। टालेमी ने जिस एरिएक एडेनन नामक प्रदेश का वर्णन किया है उसे सातवाहन राज्य मानने के अनेक आधार उपलब्ध हैं। टालेमी द्वारा वर्णित इस क्षेत्र में पाँच बंदरगाह और अठारह अर्द्धशीय नगर थे।²⁴ बहुत संभव है कि इनमें से बहुत से नगर वही हैं जिनकी जानकारी अभिलेखों या उत्खननों से मिलती है। व्यापारी लोग अपना परिचय देने

में अपने माता-पिता के नामों की अपेक्षा अपने-अपने नगरों के नाम बताने को अधिक उत्सुक दिखाई देते हैं। अनेक नैगम बताते हैं कि वे कल्याण के निवासी हैं।²⁵ हमें सोपारा²⁶ के एक नैगम, कल्याण²⁷ के एक लोहार और धेनुकाकटक²⁸ के एक बड़ई की भी जानकारी मिलती है। कुछ लोग अपने को मात्र निगमपुत्र, यानी नगरनिवासी, बताते हैं। यहां जो थोड़े-से दृष्टांत दिए गए हैं उनसे प्रकट होता है कि कारीगरों और व्यापारियों का अपने-अपने नगरों और अपने उस नागरिक जीवन पर, जिसमें उनका भी यथाशक्ति योगदान रहता होगा, कितना गर्व था। इस तरह के बहुत-से और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि व्यापारियों के लिए, वे किस जनजाति या परिवार के हैं, इसका उतना महत्त्व नहीं था जितना कि इसका कि वे किस क्षेत्र या नगर के हैं।

इनमें से कम से कम कुछ नगरों का प्रबन्ध निगमसभा करती थी। उपभदात ने प्रयानुसार इसी सभा में अपने दानपत्र की घोषणा की और पजीयन करवाया।²⁹ कभी-कभी किसी नगर के निवासी सामूहिक रूप से भी दान देते थे। अमरावती के तक्षणों में धान्यकटक नगर द्वारा दिए गए अनेक अनुदानों के उल्लेख हैं।³⁰ स्पष्ट ही निगमसभा के सदस्य व्यापारी ही होते थे, यद्यपि कुछ गृहपति भी इस हैसियत से काम करते थे।³¹ स्थानीय प्रशासन में लोकतत्त्व की प्रधानता पर अनेक लेखकों ने जोर दिया है। मगर यहाँ खासतौर से ध्यान देने लायक बात यह है कि पुरालेखों और उत्खननों से ईस्वी सन की प्रथम दो शताब्दियों में दकन और विशेषकर महाराष्ट्र में जितने अधिक नगरों के अस्तित्व का पता चलता है, प्राचीन इतिहास के अन्य किसी भी काल में इस क्षेत्र में उतने अधिक नगरों के अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती। यह तो स्पष्ट ही है कि व्यापारी लोग प्राचीन भारत में नागरिक जीवन में जितने बड़े पैमाने पर दकन में हाथ बटाते थे उतने बड़े पैमाने पर और कहीं नहीं। व्यापारियों और कारीगरों के संघों से—जिन्हें अभिलेखों में सेनि या श्रेणी और निकाय कहा गया है³²—मिलनेवाले साक्ष्यों को भी ध्यान में रखकर देखे तो कुल मिलाकर लगता है कि सातवाहनों के अधीन नागरिक जीवन का अभूतपूर्व विकास हुआ। व्यापारियों और कारीगरों के संघों का निगमसभा के साथ और निगमसभा का राज्य के साथ क्या संबंध था, इसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन जाहिर है कि ये संघ राजा के लिए आर्थिक स्थायित्व के महत्त्वपूर्ण आधार थे, और संभव है, उसे नगर प्रशासन में भी सहायता देते रहे हों। विचित्र बात है कि सातवाहनों के उत्तराधिकारियों के अधीन ईस्वी सन की छठी शताब्दी के अंत तक व्यापारियों के ऐसे संघों का कहीं कोई जिक्र देखने को नहीं मिलता।

सातवाहनों की एक और विशेषता, जो उनके शासन की समाप्ति के बाद अधिक समय तक कायम नहीं रह सकी, मातृक उत्तराधिकार की परंपरा थी। इस परंपरा का संकेत सातवाहन राजाओं के मातृनामों और ऐसी ही कुछ अन्य बातों से

मिलता है, जहाँ गुप्त और गुप्तोत्तर राजा 'पितृपादानुध्यात' (अर्थात् पिता के चरणों में अनुरक्त) कहे गए हैं, गौतमीपुत्र शातकर्ण को 'अविपनमातृसुसुक' (अनवरत मातृसेवा में रत) बताया गया है।³³ ध्यातव्य है कि गौतमीपुत्र शातकर्ण, वासिष्ठीपुत्र पुलमावि,³⁴ वासिष्ठीपुत्र शातकर्ण, गौतमीपुत्र श्री विजय शातकर्ण और गौतमीपुत्र श्री यज्ञ शातकर्ण के नामों में उनके पिता के नाम नहीं जुड़े हुए हैं। यह उत्तर भारत में गुप्तों के काल में प्रचलित प्रथा से बिलकुल भिन्न है, क्योंकि इस काल में वहाँ राजा अपने नामों के साथ पितृनाम जोड़ना और अपने पिता के वास्तविक या काल्पनिक पराक्रमों का सोत्साह वर्णन करना कभी नहीं भूलते।

चूँकि अभिलेखों से ज्ञात पूर्वतम सातवाहन राजाओं—सिगुक और कृष्ण—के नामों के साथ मातृनाम नहीं जुड़े हैं, इसलिए कुछ विद्वान ऐसा सोचते हैं कि सातवाहन राजवंश में मातृवंशीय प्रथाएं आगे चलकर समाविष्ट हुईं। लेकिन जिस स्तरक्रम (स्ट्राटिग्राफिकल पोजीशन) से महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में व्हमपुरी³⁵ नामक स्थान पर वासिष्ठीपुत्र विलिवायकुर, माढरीपुत्र सिलवकुर और गौतमीपुत्र विलिवायकुर के सिक्के प्राप्त हुए हैं, उससे यह प्रमाणित होता है कि सातवाहनों के उदय के पूर्व से ही दक्कन में मातृवंशीय प्रथाएं प्रचलित थीं। यह प्रथा सातवाहनों के समकालीन और अधीनस्थ शासक घराने महाराष्ट्रियों में भी प्रचलित थी। मातृनामिकता सामान्य लोगों में भी प्रचलित थी, जैसे कि गृहपति कौत (स्पष्टतः कृतीपुत्र) साह के नाम से प्रकट होगा।³⁶ मातृनामों का सभावित कारण मातृक उत्तराधिकार ही प्रतीत होता है, और चूँकि वंशानुगत शासन में राज्य परिवार का ही वृहत्तर रूप होता था, इसलिए राज्य के संबंध में भी उत्तराधिकार की मातृक पद्धति ही लागू होती थी। उत्तराधिकार की ठीक-ठीक रीति क्या थी, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, किंतु मातृनामिकता से संकेत मिलता है कि राजाओं को सिंहासन अपने पिता से नहीं मिलता था। नायर समाज में पुत्री को उत्तराधिकार में मिली संपत्ति का प्रबंध उसका भाई और उसके न होने पर उसका पुत्र करता है। कदाचित् यही दृष्ट्यात् गौतमीपुत्र शातकर्ण पर भी लागू होता हो, जो स्पष्ट ही अपनी माता के उत्तराधिकार में प्राप्त राज्य की व्यवस्था करता था। यदा-कदा रानी अपने वैधानिक अधिकार का आग्रह करने से भी नहीं चूकती थी। उदाहरण के लिए, अपने पुत्र के राजत्वकाल के चौबीसवें वर्ष में उसने एक कृषिभूमि के अनुदान से संबंधित आदेश सीधे गोवर्धन आहार के शासक के पास भेज दिया। राजसिंहासन का वैध अधिकारी ही ऐसा व्यवहार कर सकता था, क्योंकि अशोक के अभिलेखों में या अन्य सातवाहन अभिलेखों में हम देखते हैं कि केवल राजा ही शासकों को आदेश भेजता था।

नागनिका द्वारा संपादित वैदिक यज्ञों की लंबी और प्रभावोत्पादक सूची स्त्रियों

के लिए यज्ञादि कर्मों का वर्जन करनेवाली वैदिक तथा ब्राह्मण संस्कृति की पितृतंत्रात्मक परंपरा पर मातृतंत्र के प्रभाव की द्योतक हैं। इसके खिलाफ यह दलील दी गई है कि नागनिका ने तो ये सारे यज्ञ अपने पति के साथ संपन्न किए,³⁷ किंतु सर्वाधत अभिलेख से यह अर्थ अनुचित खींचतान करके ही निकाला गया है कि इन यज्ञों में वह अपने पति की अधांगिनी थी। वास्तव में नागनिका की गरिमामय धार्मिक स्थिति के संबंध में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, और ऐसा लगता है कि उसकी एक प्रतिमा भी सार्वजनिक रूप से प्रतिष्ठित की गई थी। इस सबके लिए उसे अनेक गांव, विपुल द्रव्य तथा बहुत-से पशु दान करने पड़े थे,³⁸ जिससे राजकोष निश्चय ही बहुत क्षीण हो गया होगा। रानी नागनिका राजकोष के धन का इस तरह व्यय कर सकती थी, यह उसकी उच्च राजनीतिक स्थिति का असंदिग्ध प्रमाण है। यद्यपि नागनिका तथा बलश्री,³⁹ इन दोनों रानियों ने अपना पूर्वैतिहास विस्तारपूर्वक दिया है, किंतु उनके भूमि अनुदान राजा द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए हैं। इन रानियों का जिन गावों पर अधिकार था वे उन्हें निवाह अनुदानों के रूप में नहीं मिले हुए थे—जैसा कि हम चाहमनों के अधीन देखते हैं—बल्कि शायद मातृक उत्तराधिकार के अंशों के रूप में प्राप्त हुए थे।

सातवाहन अधिकारियों और सामंतों की पत्नियां अपने पति का प्रशासकीय पदनाम धारण करती थीं, जिससे प्रकट होता है कि वे भी अपने पति की बराबरी की प्रतिष्ठा और प्रभाव की दावेदार थीं। महासेनापत्नी⁴⁰ और महातलवारी⁴¹ उपाधियां इसके प्रमाण हैं। एक भूमिदान शासनपत्र का प्रवर्तन करनेवाली महिला प्रतिहारि (द्वारपालिका) का भी अनोखा उदाहरण मिलता है।⁴² ये सारे तथ्य सातवाहन शासनपद्धति में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं।

यद्यपि गुप्त राजाओं के अभिलेखों में भी राजमाता का नामोल्लेख हुआ है, लेकिन बाकायक राज्य की संरक्षिका के रूप में काम करनेवाली द्वितीय चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभावती को छोड़ किसी ने भी प्रशासन में कोई उल्लेखनीय भूमिका नहीं निभाई। स्पष्ट है कि गुप्तों तथा गुप्तोत्तर राजवंशों की शासनपद्धति पर सातवाहनों की विरासत का कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा। अलबत्ता, पूर्व मध्यकालीन उड़ीसा में प्रशासन के क्षेत्र में महिलाओं ने महत्त्वपूर्ण योग दिया।

लेकिन सातवाहन राज्यव्यवस्था के अनेक तत्व चिरस्थायी सिद्ध हुए। हम गौतमीपुत्र शातकर्ण में अरोपित आलौकिक और अतिमानवीय विशिष्टताओं के उल्लेख से प्रारंभ कर सकते हैं। शक्ति और तेज में उसकी तुलना राम, केशव, अर्जुन, भीम, नृभाग, नहुष, जनमेजय, सागर, ययाति, अंबरीष, पवन, गरुड़, सिद्ध, यक्ष, राक्षस, विद्याधर, भूत, गंधर्व, चारुण, चंद्र, दिवाकर और नक्षत्र—जैसे कथा-कहानियों के पात्रों और अलौकिक शक्तियों से की गई है।⁴³ इन साम्यों से

किसी हद तक राजत्व के दैवी पक्ष का आभास मिलता है, जो गुप्त राजाओं के पुरालेखीय वर्णनों में स्पष्ट रूप से सामने आई है।

सातवाहन राजनीतिक पदाधिकारियों द्वारा 'महा' उपाधि का प्रयोग, वास्तव में, इस उपाधि के प्रयोग के प्राचीनतम दृष्टान्तों में से है। बाद में गुप्त राजाओं, अधिकारियों और सामंतों के पदनामों में इसका व्यापक प्रयोग होने लगा। सातवाहन राजा अपने को राजा ही कहते थे, हालाँकि उनके अभिलेखों में महाराज का उल्लेख मिलता है। महासेनापति, महारठी, महाभोज, महातलवार आदि अन्य पदनाम भी मिलते हैं, जो सातवाहन सामंतों की उपाधियाँ माने गए हैं। महारठी जैसे कुछ सामंत सातवाहनो की तरह न केवल मातृनाम धारण करते थे, वरन उनका स्थान भी वशानुगत होता था,⁴⁴ जिससे वे स्वतंत्र रूप से सिक्के जारी कर सकते थे⁴⁵ और ग्राम अनुदान दे सकते थे।⁴⁶ हम इन्द्रवाकुओं, चुटुसों, विष्णुकुंडनों आदि को, तथा सातवाहनों की भी अन्य शाखाओं के सदस्यों को, जो स्पष्ट ही मुख्य सातवाहनों के सामंत थे, इनमें से कुछ उपाधियाँ धारण करते देखते हैं। 'महा' उपसर्ग के प्रयोग के साथ राजपुरुषों के बीच श्रेणिबद्ध और असमान सबंधों का सूत्रपात होता है और उन उपाधियों का आरंभ होता है जो पूर्व मध्यकाल के सामंती श्रेणि विन्यास में व्यापक रूप से प्रचलित हुईं।

किंतु सातवाहन प्रशासनपद्धति का एक महत्त्वपूर्ण अंग, जिसका रूप आगे चलकर विकसित हुआ, ग्रामप्रशासन था, इस व्यवस्था में ग्रामीण लोगों की देखरेख का दायित्व या तो पुलिस और सेना को अथवा धर्मानुदानभोगियों को सौंप दिया जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन में कुछ विद्वान लोकत्व का भी समावेश देखते हैं,⁴⁷ किंतु अभिलेखों से इसका कोई संकेत नहीं मिलता। कवि हाल की 'गाथा सत्तसड' को आधार मानकर यह कहा गया है कि ग्रामीणों का अधिकार क्षेत्र पाच या दस गांवों तक भी होता था।⁴⁸ लेकिन इस ग्रंथ के पांचवें अध्याय में—रहट्टधडिय— शब्द के उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि ग्रंथ का संकलन किसी समय ईस्वी सन की नवीं शताब्दी में हुआ होगा, जब से उत्तर भारत के अभिलेखों में सिचाई के इस फारसी तरीके का जिक्र होने लगा। यद्यपि सातवाहनो के धार्मिक अनुदानों के सिलसिले में अनेक गांवों के नाम बताए गए हैं, किंतु परवर्ती काल के शासनपत्रों की तरह, उनमें ग्रामप्रधानों (हेडमैन) और गुरुजनों (एल्डर) का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ईस्वी सन की तीसरी शताब्दी के प्रथम चरण के एक अभिलेख⁴⁹ के आधार पर यह कहा गया है कि ग्राम का प्रबंध 'गामिक' या 'ग्रामिक' करता था। लेकिन जिसे 'गामिक' या 'ग्रामिक' पढ़कर ऐसा निष्कर्ष निकाला गया है वह महत्त्वपूर्ण शब्द 'गुमिक' प्रतीत होता है, जो गौलिमक का प्राकृत रूप है।⁵⁰ इस शब्द को 'गुमिक' मानना उस सदर्भ से भी संगत जान पड़ता है जिसमें गौलिमक कुमारदत्त को सातवाहणिहार के शासक महासेनापति स्कंदनाग

का अधीनस्थ बताया गया है। उसी क्षेत्र से प्राप्त एक शताब्दी बाद के एक पल्लव साम्राज्यशासन पत्र में गुप्तिक या गौलिमिक को उन राज्याधिकारियों की सूची में शामिल किया है जिन्हें अनुदान की सूचना दी गई है।⁵¹ गौलिमिक गुल्म-प्रधान होता था।⁵² और ईस्वी सन की प्रथम चार शताब्दियों के स्रोतों के अनुसार गुल्म में नौ पत्तियाँ, अर्थात् कुल मिलाकर 9 रथ, 9 हाथी, 27 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे।⁵³ बहुत संभव है कि इस काल तक युद्ध में रथों का उपयोग समाप्त हो गया था। लेकिन यह स्पष्ट है कि गुल्म सैनिक टुकड़ी थी। मनु का कहना है कि दो, तीन, पांच या सौ ग्रामों के बीच एक गुल्म रखा जाना चाहिए।⁵⁴ पुलिस और सेना के मिले-जुले रूपवाला यह दस्ता स्पष्ट ही ग्राम्य क्षेत्र के निकट रहता था और वहाँ राजशक्ति का मुख्य प्रतीक होता था। ग्रामीण क्षेत्रों की व्यवस्था के लिए गुल्म तैनात किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य ईसवी सन की तीसरी शताब्दी का है और वह मैसूर में कृष्णा के दक्षिण बैलारी जिले में प्राप्त हुआ है। इसके आधार पर यह मानना शायद उचित न हो कि इसका चलन पूर्ववर्ती काल में तथा दकन के उस पश्चिमी भाग में भी था जहाँ अधिकांश सातवाहन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ईस्वी सन की दूसरी शताब्दी में भी महासेनापति शासनपत्र का प्रारूप तैयार करने जैसे कुछ गैरसैनिक कार्य किया करता था,⁵⁵ लेकिन यह ज्ञात नहीं कि इस तरह के अधिकारी पर बड़ी-बड़ी क्षेत्रीय इकाइयों की देखरेख की जिम्मेदारी होती थी या नहीं। सुकथंकर का विचार है कि ये सैनिक अधिकारी भू-सामत थे, और इनके अधीनस्थ क्षेत्र इन्हे जागीर के तौर पर मिले हुए थे। यह अनुमान सही हो या गलत, लेकिन क्षत्रिय शासकों के रूप में सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति की प्रथा अशोक के जनपद प्रशासन से बिलकुल भिन्न है, क्योंकि हम देखते हैं कि अशोक के जनपदशासन का दायित्व 'राजुक' कहे जानेवाले उच्च गैरसैनिक पदाधिकारी पर होता था। निस्संदेह, अशोक को सीमांत क्षेत्रों के लोगों को शांत रखने की समस्या से बराबर जूझते रहना पड़ा, फिर भी उसने उन्हें सैनिक शासन के अधीन नहीं रखा।

सातवाहन ग्राम प्रशासन में बलप्रयोग का तत्त्व विद्यमान था, ऐसा निष्कर्ष धर्मानुदान भोगियों को दी गई हिदायतों से भी निकाला जा सकता है। हम देखते हैं कि अनुदत्त कृषिक्षेत्रों तथा गाँवों, दोनों को चाटो और भटो (सेना और पुलिस के लोगों) के प्रवेश तथा राजकीय अधिकारियों के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाता है। जो अनुदानभोगियों को करों की अदायगी से भी मुक्त कर दिया जाता था, किंतु शासनपत्रों में जोर करमुक्ति पर नहीं, बल्कि उपर्युक्त सुविधाओं पर ही दिया गया है। इससे यह धारणा बनती है कि राजकीय पुलिस, सैनिक, परिचर (रिटेनर) और अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में मनमाना व्यवहार करते होंगे और शोषण के कारगर साधन रहे होंगे। वाकाटक राजाओं के अधीन यह चलन कायम रहा, बल्कि इसमें

और भी तीव्रता आ गई। उन्होंने तो उन वस्तुओं का स्पष्ट निर्देश कर दिया जो ग्रामवासियों को विभिन्न राजकीय परिचरों को सुलभ करानी थीं। कालांतर से यह प्रथा पूर्व मध्यकाल की ग्रामीण शासनव्यवस्था की एक सामान्य विशेषता बन गई।

सातवाहन शासन के सैनिक स्वरूप का एक प्रमाण यह भी है कि उनके अभिलेखों में सैनिक शिविर के पर्याय कटक और स्कंधावार जैसे शब्दों का प्रयोग बार-बार हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि हरेक आहार का अपना कटक होता था। गोवर्धन आहार में स्थित बेनकटक⁵⁶ इसका एक उदाहरण है। शायद धेनुका कटक या धान्यकटक भी किसी आहार से जुड़ा कटक ही था। विजय-स्कंधावारों से शासनपत्र जारी करने का चलन, जिसका पूर्व मध्यकाल में व्यापक प्रचार हुआ, सातवाहनों ने ही आरंभ किया।

भूमि अनुदान सातवाहन ग्राम प्रशासन की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता थी। अभिलेखों से प्रकट होता है कि सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को राजस्विक तथा प्रशासनिक रियायतें देने का चलन शुरू किया। पुरालेखों में वर्णित भूमिदान का शायद सबसे प्राचीन दृष्टांत नागनिका के नानाघाट गुफालेख से उपलब्ध होता है। रानी नागनिका ने अपने वैदिक मंत्रों के पुरोहितों को दक्षिणा में कई गांव दिए।⁵⁷ लेकिन अनुदत्त गांवों में उन्हें कुछ रियायतें भी दी गईं या नहीं, इसका उल्लेख इसमें नहीं है। रियायतों का प्रथम उल्लेख ईस्वी सन की दूसरी शताब्दी के प्रथम चरण में गौतमीपुत्र शातकर्ण के दानपत्र में मिलता है। इन रियायतों में से एक यह भी है कि राज्य ने आबाद खेतों में मिलनेवाले नभक (जो शायद ऐसे सभी खेतों में नहीं ही मिलता होगा) पर अपने अधिकार का परिहार कर दिया है। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सैनिकों, पुलिस के लोगों तथा राजपरिचरों को आदेश दिया गया है कि वे अनुदत्त गांवों या खेत के प्रबंध में हस्तक्षेप न करें। इस प्रकार अनुदत्त क्षेत्र पूर्णतः धार्मिक दानभोगियों के हाथों में चला जाता था।

ईस्वी सन की दूसरी शताब्दी के सातवाहन अभिलेखों में प्रयुक्त सर्वजाति परिहार⁵⁸ शब्द-समुच्चय से प्रकट होता है कि अनुदानभोगियों को सभी प्रकार की रियायतें दी जाती थीं। राजकीय शासनपत्र के अर्थ में परिहार की जो परिभाषा कौटिल्य ने की है उसके अनुसार उससे जाति विशेष, नगरविशेष, ग्रामविशेष या प्रदेशविशेष पर की गई राजकृपा का बोध होता है।⁵⁹ करमुक्ति के अर्थ में परिहार की सिफेपरिभाषा नए वृत्त इलाकों के किसानों के लिए⁶⁰ तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में नायकों और व्यापारियों के लिए भी की गई है।⁶¹ सिचाई साधनों का जीर्णोद्धार करने वालों को भी इसी अर्थ में पांच वर्षों के लिए परिहार प्रदान करने को कहा गया है।⁶² 'अर्थशास्त्र' से हमें परिहार का उपभोग करनेवाले गांवों⁶⁰ और परिहार के

सहारे ही जीवनयापन करनेवाले राजकुपापात्रों⁶⁴ के उल्लेख भी देखने को मिलते हैं। कौटिल्य विशुद्ध रूप से घर्मानिरपेक्ष उद्देश्य से अर्थात् अंततः राजकीय संसाधनों की वृद्धि के प्रयोजन से—परिहार की सिफारिश करते हैं। किंतु सातवाहन अभिलेखों में केवल धार्मिक प्रयोजनों से प्रदत्त परिहारों का उल्लेख है, और सिर्फ चार-पांच मर्दों में रियायत दी गई है।⁶⁵ ईस्वी सन की चौथी शताब्दी के एक पल्लव अभिलेख में अलग-अलग प्रकार के परिहारों (अष्टादश जातिपरिहार) का उल्लेख मिलता है।⁶⁶ इस अभिलेख के अनुसार सातवाहन राष्ट्र में भी इन परिहारों का प्रचलन था।⁶⁷ लेकिन हम निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि ईस्वी सन की तीसरी शताब्दी के प्रारंभ से, जबकि यह क्षेत्र सातवाहनों के अधीन आया, कृषकों से ये सारे कर वसूल किए जाते थे या नहीं।

राजस्विक और प्रशासनिक अधिकारों का पूर्ण और स्थायी परिहार किया जाता रहा हो, ऐसी बात भी नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वासिष्ठीपुत्र पुलुमावि ने बौद्ध भिक्षुओं के एक समूह को प्रदत्त गांव उनसे लेकर दूसरे समूह को दान दिया।⁶⁸ फिर, जान पड़ता है, गौतमीपुत्र ने भिक्षुओं को प्रदत्त एक क्षेत्र उनसे इस आधार पर वापस ले लिया कि वे उसमें खेती नहीं करते थे और गांव में लोग निवास नहीं कर रहे थे। इसके बदले उन्हें नगरसीमा पर दूसरी जमीन दी गई।⁶⁹ जो भी हो, सातवाहन राज्य में स्थायी भूमि अनुदान नहीं दिया जाता था। वैसे तो इस काल में भी हमें अक्षयनीवि⁷⁰ धृति (टेन्पोर) का उल्लेख मिलता है, लेकिन अभी इसका अर्थ किसी क्षेत्र या वस्तु का स्थायी अनुदान नहीं, बल्कि अनुदत्त क्षेत्र या वस्तु का अक्षय स्वरूप ही मानना चाहिए।

स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए सातवाहनों ने दंडप्रयोग के साथ-साथ भिक्षुओं और पुरोहितों को अनुदान देने के उपाय से भी काम लिया। बौद्ध भिक्षुओं ने, जो अभिलेखों के अनुसार प्राचीनतम भूमि अनुदान-भोगी प्रतीत होते हैं, निश्चय ही सामान्य लोगों के बीच शांति और सदाचरण के नियमों का प्रचार किया होगा, जिससे प्रजा द्वारा राजसत्ता तथा समाजव्यवस्था को चुनौती दिए जाने के प्रसंग बहुत कम हो गए होंगे। वर्णव्यवस्था के नियमों का पालन करवाने के लिए उत्सुक ब्राह्मणों से गौतमीपुत्र का भी कुछ ऐसा ही प्रयोजन सिद्ध होता होगा। एक अभिलेख में शातकर्णिक को एकमात्र ब्राह्मण और वर्णसंकरता का निवारक कहा है। सातवाहन लोग बनावटी प्रतीत होते हैं, और शायद यही कारण था कि उन्होंने ब्राह्मणव्यवस्था को इतना प्रबल समर्थन दिया। सातवाहन अभिलेखों में उल्लिखित चारों वर्ण सातवाहनों के राज्य में, शायद, समान रूप से सुस्थापित नहीं हो पाए थे और संभव है कि वर्णव्यवस्था की रक्षा के लिए राजा को वास्तव में सिर्फ शूद्रों को अनुशासित करने का काम ही करना पड़ता हो, हालांकि गौतमीपुत्र का दावा है कि उसने धर्मिय

राजाओं को नीचा दिखाया। इस राजा ने अपने जिम्मे जो कर्तव्य लिया है वह वही है जो कौटिल्य ने राजा के लिए निर्धारित किया है। आगे चलकर अभिलेखों में यही दावा गुप्त राजा, हर्षवर्धन और अन्य शासक भी करते हैं। लेकिन प्रचलित समाजव्यवस्था को कायम रखकर राजनीतिक स्थिरता में योगदान देने के राजकीय दायित्व पर सबसे पहले सातवाहनों ने ही जोर दिया।

इस अध्ययन से सातवाहनों के राजनीतिक संगठन की जो तसवीर सामने आती है वह अधूरी है। हमें उनकी न्याय पद्धति की कोई भी जानकारी नहीं है, नागरिक प्रशासन की बहुत थोड़ी, तथा राजस्व और सैनिक संगठन की अपर्याप्त जानकारी ही सुलभ है। दूसरी और तीसरी शताब्दियों के अभिलेखों से पता चलता है कि उनका राज्य 'आहारो' और 'ग्रामो' में विभाजित था। 'आहार' ऊपर के स्तर की ईकाई था और गाव नीचे की स्तर की। 'आहार' शायद अमात्य या महासेनापति के अधीन होता था और गाव गौलिमक के अधीन। क्षेत्रीय इकाइयों के प्रधान के रूप में दो परवर्ती अधिकारियों का उल्लेख हमें बैलारी जिले में ईस्वी सन की तीसरी शताब्दी में मिलता है। इसलिए ऐसा मानना कठिन है कि यह साफ-सुथरी क्षेत्रीय व्यवस्था संपूर्ण सातवाहन राज्य में और पूरे सातवाहन शासनकाल में लागू थी। अनेक पुरालेखीय साक्ष्यों से यह संकेत मिलता है कि भिक्षु और व्यापारी सातवाहन राज्यव्यवस्था के स्तंभरूप थे। लेकिन प्रशासन में उनका वास्तविक योगदान क्या था, यह हम नहीं बता सकते। संभवतः भिक्षु, उन्हें जो विपुल अनुदान मिलते थे, उनके बदले में लोगों के बीच शांति का प्रचार करते थे और व्यापारी इनके तथा राज्य के अन्य खर्चों के लिए आवश्यक साधन जुटाते थे।

सातवाहन शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसका दंडात्मक, अर्थात् सैनिक स्वरूप है, जिसका अंदाजा एक तो इस बात से मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस के लोगों तथा सैनिकों के प्रवेश और हस्तक्षेप के वर्जन का उल्लेख अनुदानों में दी गई एक प्रमुख रियायत की तरह किया गया है, और दूसरे, इससे कि हम प्रशासनाधिकारियों के लिए महासेनापति और गौलिमक जैसे सैनिक पदनामों का चलन देखते हैं।

सातवाहन प्रशासन पद्धति मौयों और गुप्तों के बीच, तथा उत्तर और दक्षिण के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी प्रतीत होती है। सातवाहनो ने अशोक के प्रशासन के कुछेक तत्व कायम रखे, किंतु साथ ही, उन्होंने अनेक नए और महत्वपूर्ण तत्व समाविष्ट भी किए, जिन्हें आगे बाकायकों और गुप्तों में अपना लिया। उनके शासन में महिलाओं और व्यापारियों द्वारा निर्माई जानेवाली भूमिका अधिक दिनों तक कायम नहीं रही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों को सैनिक शासन में रखने तथा अनुदान में राजस्विक और प्रशासनिक अधिकारों के परिहार की प्रथाएँ उत्तर और दक्षिण दोनों ही दिशाओं में फैली। इस दृष्टि से पल्लव प्रशासनपद्धति को सातवाहनो की

विरासत का दक्षिण दिशा में हुआ प्रसार माना जा सकता है। पल्लवों ने गुल्म प्रशासनपद्धति और परिहारों का सिलसिला कायम ही नहीं रखा, बल्कि इनके शासन में चौथी सदी में परिहारों की संख्या अठारह और छठी सदी में पैंतीस तक पहुँच गई।

संदर्भ और टिप्पणियाँ

- 1 सिलेक्ट इन्सक्रिप्शंस, II, स 86, पंक्ति 10
- 2 एच सी रायचौधरी का विचार है कि सातवाहन काल के बाद आहार शायद लुप्त हो गए (जी याजदानी-संपादित, अर्ली हिस्ट्री ऑफ़ दि देकन, भाग I-IV पृ 45) लेकिन अभिलेखों से इस बात का समर्थन नहीं होता
- 3 जनपदे सातवाहणहारे, से इ, II, स 90, पंक्ति 2
- 4 'स्थानीय' में 800 गाव पड़ते थे (अर्थ II-2 1) यह जनपद का अंग था (अर्थ, II 2 3) जनपद राजस्व के प्रयोजनार्थ चार इकाइयों में विभाजित होता था। (II 2 34) हर राजस्विक इकाई शायद स्थानीय के बराबर होती थी
- 5 वही, स 75, पंक्तिया 1-2
- 6 से इ II, स 83, पंक्ति 2
- 7 वही, पंक्ति 5
- 8 वही, स 84, पंक्ति 1
- 9 वही, स 87, पंक्ति 2
- 10 ल्यूडर्स लिस्ट, न. 1105
- 11 वही, 994
- 12 क्लेक्टेट वार्स ऑफ़ आर जी भंडारकर II, 242
- 13 से इ, II, स 87, 14 के संबंध में सरकार का पाठ 'बटिक खेहि' है जिसका संस्कृत रूप वह पट्टिकापालकें बताते हैं।
- 14 से इ, II, स 82
- 15 जी याजदानी, सधा, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ़ दि देकन, I VI, पृ 134, पादटिप्पणी 2
- 16 से इ, II, स 85, पंक्ति 3
- 17 वही, II, स 86, पंक्ति 11
- 18 वही, स 85, पंक्ति 3
- 19 वही
- 20 ल्यूडर्स लिस्ट, स 996, 1033 स 1141 में 'भाडाकारिकय' शब्द आया है
- 21 वही, 987
- 22 वही
- 23 से. इ II, स 59, पंक्ति 2
- 24 ज आं हि सो, xxii (1952-54), 69
25. ल्यूडर्स लिस्ट, स 1000-1, 1024 आदि
26. स 995

- 27 स. 1032.
- 28 स 1092
- 29 से इ, II स. 58, पंक्ति 4
- 30 सी शिवराममूर्ति, अमरावती स्कल्पघर्ष इन द मद्रास गवर्नमेंट म्यूजियम (ब्रिटेन ऑफ द मद्रास गवर्नमेंट म्यूजियम, न्यू सि जेनरल सेवरान, IV मद्रास 1956), 275, 285.
- 31 वही एम बालने, 'शातशाहनाज एंड द कटेपरी क्षत्रपाज', ज. म. ब्रा. ई. ए सी, न्यू सि, 1, 57, अर्ली हिस्ट्री ऑफ द देकन, भाग I-IV, पृ. 135 पर उद्धृत.
- 32 ल्यूडर्स लिस्ट, स 1137, 1180, 1133, 1165.
- 33 से इ, II, स 86 प 4
- 34 वासिष्ठीपुत्र पुलभावि ने 'पितृस्नेहवशा' एक गाव का दान किया था से इ II, सं 86, पंक्ति 11
- 35 परमेश्वरी लाल गुप्त, 'क्याइस ऑफ बहमपुरी एक्सकेवेरास (1945-46)' दि ब्रिटेन ऑफ दि देकन कालेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिल्द 21, पृ 45-47.
- 36 से इ II, स 90, प 3
- 37 डी सी सरकार, से इ (द्वितीय सस्क), पृ 97, पादटिप्पणी 1.
- 38 से इ, II, स 82
- 39 वही, स 86
- 40 वही, स 89, पंक्ति 2
- 41 वही स 98, पंक्ति 9 यह ईस्वी सन् की तीसरी सदी के उत्तरार्ध का इस्वाकू अभिलेख है
- 42 से इ, II, स 84, पंक्ति 6 इसे जिस रूप में डी सी सरकार ने पढ़ा है उसके आधार पर, तथा द्वितीय सस्करण के पृष्ठ 201 पर दी गई उसी की पादटिप्पणी के अनुसार, इस अभिलेख का यही अर्थ निकलता है
- 43 से इ, II, स 86, पंक्तिया 7-9
- 44 से इ, II, स 85, पंक्तिया 2-3
- 45 परमेश्वरी लाल गुप्त, दि ब्रिटेन ऑफ दि देकन कालेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिल्द 21, 42-45
- 46 से इ, II, स 85, पंक्तिया 2-3.
- 47 जी याजदानी, सपा, अर्ली हिस्ट्री ऑफ दि देकन, भाग I-IV, पृ. 135.
- 48 वही
- 49 से इ, II, स 90
- 50 ए इ, XIV 155, पादटिप्पणी 5
- 51 वही, III, स 65, पंक्ति 5
- 52 से इ, II स 90, पंक्ति 13 डी सी सरकार इसे 'गमिक' कहते हैं। सुकथकार इसे 'गुमिक-गौत्मिक' (ए ई, XIV 155, पा. टि 5) कहते हैं, जिसे डी डी कोलाबी ने अपनी पुस्तक एन इट्रोडक्शन टु दि स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, पृ 276 पर स्वीकार किया है.
- 53 कोलाबी की पूर्वोद्धृत पुस्तक के पृ 276 पर उद्धृत महाभारत, 1-2. 15-17, और अमरकेशरा, II, 8-10 11.
- 54 VII 114
- 55 से इ, II, स 87, पंक्ति 4
- 56 से इ, II, स 83, पंक्ति 1
- 57 से इ II, स. 82

- 58 वही, स 83, पक्ति 4
- 59 अर्थ II 10
- 60 वही II.1.
61. वही, II 16
- 62 वही, III 9
63. वही, II 35.
- 64 वही, II 37
- 65 से द्, II, स. 83, पक्तिया 3-4.
66. वही, III स 65, पक्तिया 31-26
- 67 वही, I 27
- 68 वही, II स 87, पक्तिया 2-4
- 69 वही, स 84, पक्तिया 3-5
- 70 वही, स 87, पक्तिया 2